

पुणे,

जी उद्योगांच्या पत्र पत्र,
उद्योग विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन ।

हेतू,

विभाग,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षण परिषद,
शिक्षण क्षेत्र-2, अजमेर रोड,
पुणे विभाग,
नई दिल्ली ।

शिक्षण [7] अनुदान

संख्या : दिनांक 2 मार्च, 2001

विषय:- सर्वोच्च न्यायालयाने, गतवर्षी, एटा वी सीपीएनएन
नई दिल्ली हे समिती हे अनुदान हे अनुदान-यत्र दिले जाने
हे समिती वें ।

संदर्भ,

अनुदान विभाग वर असे म्हणून का निदेश द्या हे कि
सर्वोच्च न्यायालयाने, गतवर्षी, एटा वी सीपीएनएन, नई दिल्ली
हे समिती हे अनुदान हे अनुदान-यत्र दिले जाने वें इत राज्य सरकार
की निष्पत्तीबद्दल प्रतिबन्धां हे उपाय अनुदान नही हे :-

- [1] विभागाच्या वी संशोधन तंत्रावरील का तमय तमय पर नवीनीकरण
कराया जायेना।
- [2] विभागाच्या वी अनुदान समिती वें शिक्षण निदेशक द्वारा नामित
एक सदस्य होना ।
- [3] विभागाच्या वें असे ते असे एक प्रतिभात स्थान अनुदान वी अनुदान
करावत हे असे वें विले सुरक्षित रहेगे और उभरे उत्तर प्रदेश
माध्यमिक शिक्षण परिषद द्वारा संशोधन विभागाच्या वें विभिन्न
अशांती वें विले निर्धारित शुल्क ते अशांत शुल्क नही किया
जायेना।
- [4] संस्था द्वारा राज्य सरकार ते अति अनुदान वी वी नही की
जायेनी और यदि पूर्व वें विभागाच्या माध्यमिक शिक्षण परिषद ते
अशांत वें शिक्षण परिषद ते मान्यता प्राप्त हे तथा
विभागाच्या वी समिती केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षण परिषद/
ऑफिस फार दि इन्डियन एजुकेटिन्स इन्व्हायनेशन, नई
दिल्ली ते प्राप्त होती हे तो उत परीक्षा कर्त ते उत केन्द्रीय

परिषदों की सम्बन्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।

§5§ संस्था, गीर्वाण एवं गीर्वाणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय तहातया, प्राप्त गीर्वाण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य शर्तों से कम वेतनमान तथा अन्य शर्तों नहीं दिये जायेंगे।

§6§ कर्मचारियों की सेवा ²¹⁶ ~~सेवा~~ बनायी जायेगी और उन्हें तहायता प्राप्त अगातकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा निवृत्ति का साम उपलब्ध कराये जायेंगे।

§7§ राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्मित किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।

§8§ विधानमय का रिजार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।

§9§ उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

2- उक्त प्रतिबन्धनों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धनों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की छूट या गिर्वाणता घटती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

मावदीय,

! अखिलेश एन्ड गुप्त !
अनु सचिव।

पृ० सं० ३३।।।/१५-७-१६।३।/२००१ तददिनांक

प्रेक्षित :- प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाय एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, आगरा।
- 3- जिला विधानमय निरीहाक, सटा।
- 4- निरीहाक, आंगन भारतीय विधानमय, उ० प्र०, लखनऊ।
- 5- प्रबन्धक, सत० प्र० सत० प्र० विधिक स्कूल, शातगज, सटा।

आज्ञा से,

